



2026:AHC: 164140-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2738/1987

बच्चू सिंह

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

लाल साहब सिंह

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : सैफुल इस्लाम सिद्दीकी, अली हसन, सैफुल इस्लाम सिद्दीकी (ए.सी.)

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या- 42

माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. वर्तमान अपील अपीलार्थियों द्वारा दाखिल की गई है, जो सत्र परीक्षण संख्या 68 वर्ष 1987 (राज्य बनाम बचनू सिंह और अन्य) में पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय दिनांक 20.11.1987 से व्यथित हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थियों का विचारण किया गया और दोहरे हत्याकांड के वाद में दोषसिद्ध किया गया तथा उमा शंकर और बबाऊ की हत्या के लिए दो मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत सात वर्ष का कठोर कारावास और उमा शंकर तथा बबाऊ के शवों को ठिकाने लगाने से संबंधित दो वादों में भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के अंतर्गत अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी थी। सभी सजाएं साथ-साथ चलनी थीं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पी.डब्ल्यू.-1 श्रीनेथ, पुत्र रामावतार मुसहर, निवासी ग्राम सराय बिक्रम, जो थाना बरसाठी, जिला जौनपुर के अंतर्गत आता है, ने 21.02.1987 को सुबह 10.30 बजे थाना बरसाठी में पुलिस को एक लिखित शिकायत (प्रदर्श क-1) सौंपी, जिसमें खुलासा किया गया कि 20-21 फरवरी, 1987 की दरमियानी रात लगभग 8 बजे, अभियुक्त बचनू सिंह, जिलेदार पांडेय, रामभुवन सिंह, बगई @ जिलाजीत यादव सूचनादाता के डेरे पर आए और गूगे, श्रीमती चमेला (पी.डब्ल्यू.-2), श्रीमती पियारी (पी.डब्ल्यू.-3) की उपस्थिति में बबाऊ और उमा शंकर मुसहर को जबरन ले गए। सूचनादाता पी.डब्ल्यू.-1 है, जिसका कहना है कि उसके परिवार के सदस्यों ने अभियुक्तों को मृतकों को ले जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और इसके बजाय पी.डब्ल्यू.-1 और उसके परिवार के साथ-साथ उनकी संपत्ति को भी जान से मारने और नुकसान पहुंचाने की धमकी दिया। शिकायत (प्रदर्श क-1) में यह भी खुलासा किया गया है कि अभियुक्त 1000/- रुपये की मांग कर रहे थे जिसका भुगतान करने से पीड़ितों ने इनकार कर दिया था और इसलिए, अभियुक्त पीड़ितों को अपने साथ ले गए। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान 21.02.1987 को ही दर्ज किए गए थे। तत्पश्चात, उपर्युक्त मृतकों के शव 22.02.1987 को एक कुएं से बरामद किए गए। शवों की बरामदगी के पश्चात, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और दोनों शवों पर धारदार हथियारों से कारित कई छुरा घोंपने और कटे हुए घाव पाए गए और उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्टों को प्रदर्श क-5 और क-6 के रूप में सिद्ध किया गया है।

3. विद्वान न्याय मित्र श्री सैफुल इस्लाम सिद्दीकी, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की ओर से इस वाद में बहस करने के लिए नियुक्त किया गया है, ने शुरुआत में ही इस न्यायालय के ध्यान में लाया कि एक अपीलार्थी की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है (अपीलार्थी संख्या 2-जिलेदार पांडेय) और इसलिए, उक्त अपीलार्थी के विरुद्ध अपील उपशमित हो जाती है। अन्य के संबंध में, विद्वान न्याय मित्र ने तर्क दिया है कि अपीलार्थियों को इस वाद में झूठा फंसाया गया है और अपीलार्थियों द्वारा दो मृतकों की हत्या स्थापित करने के लिए कोई चश्मदीद गवाह का साक्ष्य नहीं है। अपीलार्थियों में से एक ने यह भी एक सामान्य बचाव लिया है कि एक तीसरे व्यक्ति के साथ उसकी दुश्मनी के कारण, गवाहों को उस तीसरे व्यक्ति द्वारा अपीलार्थियों को झूठा फंसाने के लिए प्रभावित किया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि अभियोजन पक्ष के मामले का मूल यह है कि अपीलार्थी मृतकों को उनके घर से जबरन ले गए, जिसके पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 गवाह हैं। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक साथ अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य कमजोर है क्योंकि मृतकों के शव कथित तौर पर अपीलार्थियों द्वारा ले जाए जाने के 24 घंटे से अधिक समय बाद बरामद किए गए हैं। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य को पढ़ा है और कई छोटी विसंगतियों के आधार पर इस न्यायालय को यह समझाने का प्रयास किया है कि उनके बयान विश्वसनीय क्यों नहीं हैं। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि इन गवाहों ने कहा है कि अपीलार्थी धारदार हथियारों और आग्नेयास्त्रों से लैस थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा नहीं कहा है। इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट बनाने वाले, जो पी.डब्ल्यू.-1 है, का आमना-सामना न्यायालय में उसके इस बयान को झूठा साबित करता है कि जब ये अपीलार्थी घर में घुसे तो वे हथियारबंद थे।

5. विद्वान न्याय मित्र ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक का भी उल्लेख किया है, जो एक लोहार है, जिसके पास पी.डब्ल्यू.-1 का कहना है कि वह गया था और जिससे शिकायत लिखवाई गई थी, जिसे 21.02.1987 को पुलिस को सौंपा गया था। विद्वान न्याय मित्र ने पी.डब्ल्यू.-1 की जिरह के उस हिस्से का भी उल्लेख किया है, जब पी.डब्ल्यू.-1 कहता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक, लोहार ने शिकायत अपने शब्दों में लिखी और जो उसे सही लगा उसके अनुसार लिखा। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है कि 21.02.1987 को पुलिस को सौंपी गई शिकायत, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, पी.डब्ल्यू.-1 के शब्दों में नहीं थी और यह लोहार द्वारा लिखी गई एक कल्पना थी, जिसका कभी गवाह के रूप में परीक्षण नहीं किया गया।

6. मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों के संबंध में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थियों से कभी कोई हथियार जब्त नहीं किया गया, जिससे यह पता चलता कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें उन हथियारों से कारित की जा सकती थीं। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थियों को मृतक को चोटें पहुंचाने से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. सुश्री दिव्या ओझा ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है। उन्होंने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 22.02.1987 को सुबह 10.30 बजे दर्ज की गई थी, जबकि घटना 20-21 फरवरी, 1987 की दरमियानी रात 8 बजे हुई थी, जहां अपीलार्थी मृतकों को ले गए थे। दूसरे शब्दों में, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि यह प्रासंगिक है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दो मृतकों के अपहरण के लिए दर्ज की गई थी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रामाणिकता को परिलक्षित करता है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के समय शव बरामद नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त, विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करती हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थियों के नाम उन व्यक्तियों के रूप में दर्ज हैं जो मृतकों को ले गए थे।

8. इसके अतिरिक्त, विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करती हैं कि अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य पूरी तरह से लागू होगा क्योंकि अपीलार्थियों द्वारा मृतकों को जबरन ले जाने के तुरंत बाद पुलिस को अपहरण की सूचना दी गई थी और उसके बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के ठीक अगले दिन, मृतकों के शव बरामद किए गए थे। इन परिस्थितियों में, विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करती हैं कि यह स्पष्ट करना अपीलार्थियों का काम है कि यदि वे निर्दोष हैं तो उन्होंने दोनों मृतकों को कहाँ छोड़ा था और उन्होंने दोनों मृतकों को किसकी संगति में छोड़ा था और यह तथ्य अपीलार्थियों द्वारा सिद्ध किया जाना था न कि अभियोजन पक्ष द्वारा किया जाना था।

9. पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के बयानों में विसंगतियों के संबंध में, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया है कि उक्त गवाह देहाती व्यक्ति हैं, निरक्षर हैं और आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं, और इसलिए, उनके बयानों में कोई भी मामूली विसंगतियाँ स्वाभाविक हैं, जो केवल मृतकों को अपीलार्थियों द्वारा ले जाए जाने के मूल मुद्दे पर उनके बयानों को मजबूत करने का काम करती हैं, जिसका जिरह में खंडन नहीं किया गया है।

10. पी.डब्ल्यू.-1 के बयान और जिरह के संबंध में, जहां वह कहता है कि लोहार ने अपने आप शिकायत लिखी थी और इसे पी.डब्ल्यू.-1 को दिया था, विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करती हैं कि इसे गांव में होने वाली बातचीत और उस बोली की पृष्ठभूमि में सराहा जाना चाहिए जिसमें बातचीत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होती है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा लोहार को प्रकरण के तथ्यात्मक पहलुओं की व्यापक रूपरेखा दिए जाने के बाद, लोहार द्वारा शिकायत में उन्हें एक समझने योग्य रूप में रखा गया था। हालांकि, उनके अनुसार, यह अपीलार्थियों के विरुद्ध मामले को कमजोर नहीं करता है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो कहा गया है वह अपीलार्थियों द्वारा मृतकों के अपहरण से संबंधित है, जिसे पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा न्यायालय में उनकी गवाही में सिद्ध किया गया है।

11. अपराध से संबंधित हथियारों की जब्ती न होने के संबंध में, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया है कि यह हर मामले में हमेशा घातक नहीं होता है और वर्तमान मामले जैसे मामले में तो और भी नहीं जहां मृतक को पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 की उपस्थिति में ले जाया गया है, जिसकी उन्होंने गवाही दी है और अपीलार्थियों द्वारा ले जाए जा रहे हथियारों की प्रकृति भी बताई है। पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा उल्लेखित हथियारों में धारदार प्रकार के भी हैं, जिनके बारे में विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया है कि वे दोनों मृतकों के शरीर पर पाई गई सभी चोटों को कारित करने में सक्षम हैं। यह आगे कहा गया है कि अपराध करने के बाद अपराध करने के लिए इस्तेमाल की गई वस्तु को ठिकाने लगाना या उससे छुटकारा पाना अपराधी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसलिए, इसकी जब्ती न होने को हर प्रकरण में घातक नहीं कहा जा सकता है। इस वाद में, घटना के उद्देश्य के संबंध में, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थियों ने मृतकों से 1000 रुपये के भुगतान की मांग की थी और उनके द्वारा इसका भुगतान करने से इनकार करने पर, अभियुक्तों द्वारा उन्हें ले जाया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि मृतकों के साथ एक अपराध के निपटारे में अपीलार्थियों द्वारा किए गए खर्चों को चुकाने के लिए 1000 रुपये की मांग की गई थी, जो पूर्व दुश्मनी को प्रकट करता है।

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

13. इस वाद में, अभियोजन पक्ष की कहानी का मूल 20-21 फरवरी, 1987 की दरमियानी रात को मृतकों का अपहरण है, जो पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 की उपस्थिति में हुआ था। पी.डब्ल्यू.-1 का उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर खंडन करने का प्रयास किया गया है जहां विद्वान न्याय मित्र ने प्रस्तुत किया है कि जब वे घर में घुसे तो अपीलार्थियों के हथियारबंद

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होने का कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि, पी.डब्ल्यू.-1 के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान को देखने पर, जो 21.02.1987 को ही दोपहर लगभग 12 बजे दर्ज किया गया था, उसने उक्त 161 के बयान में ऐसा कहा है। हालांकि, यह न्यायालय पुष्टि के लिए उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, बल्कि केवल यह दिखाने के उद्देश्य से कि बचाव पक्ष ने कभी भी पी.डब्ल्यू.-1 का उसके 161 के बयान से आमना-सामना नहीं कराया। विद्वान न्याय मित्र द्वारा रखे गए इस तर्क के संबंध में कि यह तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में नदारद है, यह स्थापित विधि है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संपूर्ण अभियोजन पक्ष के मामले का कोई सार-संग्रह या विश्वकोश नहीं है। यह केवल एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करने के लिए है ताकि पुलिस विवेचना शुरू करने में सक्षम हो सके। इसलिए, यह स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू.-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में जो कहा है, वह 161 के बयान में कोई चूक नहीं थी, अन्यथा गवाह का इससे आमना-सामना कराया गया होता।

14. यह तथ्य कि अपीलार्थी हथियारबंद थे, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा भी पुष्ट किया गया है, जो यहां अपीलार्थियों द्वारा मृतकों के अपहरण के गवाह भी हैं। इन गवाहों का भी अपहरण से संबंधित तात्त्विक विवरणों पर खंडन नहीं किया गया है।

15. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान न्याय मित्र द्वारा रखे गए तर्कों के संबंध में कि अपीलार्थियों को अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने और मृतकों के शवों की बरामदगी के बीच एक लंबी अवधि बीत गई। यहां यह न्यायालय "साथ में अंतिम बार देखे जाने)" और "अभिरक्षा में अंतिम बार देखे जाने" के बीच अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक समझता है। यह अंतर यद्यपि मामूली प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक है। जब किसी व्यक्ति को अंतिम बार किसी अन्य की संगति में देखा जाता है, तो यह मृतक की ओर से स्वेच्छा का एक तत्व दर्शाता है, जिसे संदिग्ध की संगति में अंतिम बार देखा गया था क्योंकि कोई प्रताड़ना/दबाव नहीं था। हालांकि, अभियुक्त की अभिरक्षा में अंतिम बार देखे जाने का अर्थ पूरी तरह से अलग है। यह यह परिलक्षित करता है कि मृतक, जिसे अंतिम बार अभियुक्त की अभिरक्षा में देखा गया था, को अपनी इच्छा से कहीं भी जाने की स्वतंत्रता या अपनी मर्जी नहीं थी और जहां तक उसकी स्वतंत्रता का संबंध है वह बाध्य था। ऐसी स्थिति में, जहां किसी व्यक्ति को अंतिम बार अभियुक्त की अभिरक्षा में देखा जाता है जैसा कि वर्तमान वाद में है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू होगी, विशेषकर तब जब मृतक के शवों को अभियुक्तों की अभिरक्षा में अंतिम बार देखे जाने के बाद बरामद किया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जाता है। ऐसी स्थिति में, यह स्थापित करना बचाव पक्ष का काम होगा कि उन्होंने मृतकों को कहां छोड़ा था, और इस आशय का कुछ साक्ष्य होना चाहिए कि दूसरों ने मृतकों को अपीलार्थियों द्वारा छोड़े जाते हुए देखा हो, जिन्होंने उन्हें अभिरक्षा में रखा था और मृतक अभियुक्तों की निकटता से दूर चले गए हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब अपीलार्थियों द्वारा पीड़ितों को जबरन अभिरक्षा में ले लिया जाता है, तो उनके साथ क्या हुआ, यह विशेष रूप से केवल अपीलार्थियों के ज्ञान में होता है और किसी अन्य व्यक्ति के नहीं होता है।

16. अपीलार्थियों ने एक समानांतर परिकल्पना स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता हो कि उन्हें कभी उनकी अभिरक्षा से रिहा किया गया था, ताकि यह संदेह पैदा हो सके कि अपीलार्थियों द्वारा मृतकों को रिहा करने और उनके शव मिलने के बीच कोई मध्यवर्ती घटना हुई थी जो न्यायालय को यह आशंका करा सके कि शायद किसी और ने अपराध किया होगा। जहां तक वर्तमान वाद का संबंध है, ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं है।

17. गवाह समाज के जिस तबके से आते हैं, उसके संबंध में भी यहां उल्लेख करना आवश्यक है। उस संबंध में, यह न्यायालय पी.डब्ल्यू.-3 श्रीमती पियारी की गवाही के उस हिस्से को अक्षरशः प्रस्तुत करना आवश्यक समझता है, जो उन हथियारों से संबंधित है जिन्हें उसने अपीलार्थियों द्वारा ले जाते हुए देखा था, जहां वह कहती है **“मल्लिमान हाजिर अदालत मेरे डेरे पर आये यह लोग चाकू व हथियार जिसमे गोली भरा रहता है लिये थे”**

अभियोजन पक्ष की गवाह के ज्ञान का स्तर स्पष्ट है, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता कि किसी आग्नेयास्त्र का वर्णन कैसे किया जाए, चाहे वह आग्नेयास्त्र को तमंचा या पिस्तौल या रिवाल्वर कहे। इसके बजाय वह इसे एक ऐसे हथियार के रूप में वर्णित करती है, जिसमें गोले डाले जाते हैं।

18. इसलिए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध वाद को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है। अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, जो उन्हें उनकी सजा के शेष भाग को पूरा करने के लिए जेल भेज देगा। यदि वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध है कि वे उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें जेल भेजने के लिए ऐसी दंडात्मक कार्यवाहियों का सहारा लें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. न्यायालय विद्वान न्याय मित्र श्री सैफुल इस्लाम सिद्दीकी द्वारा किए गए प्रयासों के लिए अपनी सराहना दर्ज करना चाहता है और विधिक सेवा प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि उन्हें न्यायालय में उनकी सहायता के लिए 25,000/- रुपये का भुगतान किया जाए।

5 अगस्त, 2026

नोमान

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”